Schedule II" the words and figures "The Central Government or the State Government, as the case may be, may, by notification, declare any wild animal specified in Schedule II" shall be substituted;".

The question was put and the motion was negatived.

Clause 38 was added to the Bill.

Clauses 39 to 41 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Bhupender Yadav to move that the Bill be passed.

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय उपसभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि विधेयक को पारित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now the next Business is the Energy Conservation (Amendment) Bill, 2022. Shri Raj Kumar Singh to move a motion for consideration of the Energy Conservation (Amendment) Bill, 2022.

The Energy Conservation (Amendment) Bill, 2022

THE MINISTER OF POWER; AND THE MINISTER OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI RAJ KUMAR SINGH): Sir, I move:

"That the Bill further to amend the Energy Conservation Act, 2001, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

श्री उपसभापति: माननीय मंत्री जी, यदि आप कुछ बोलना चाहते हैं तो इस बिल के संबंध में बताएं।

श्री राज कुमार सिंह: उपसभापति जी, बीते कुछ दशकों से पर्यावरण में डिटिरिओरेशन की चिंता पूरी दुनिया को सताती रही है। इसके लिए कई सारे कांफ्रेन्सेज़ हुए-जैसे क्योटो हुआ, उसके बाद CoP - जो कांफ्रेन्स ऑफ पार्टीज़ for combating climate change के अंतर्गत कांफ्रेन्स ऑफ दि पार्टीज़ है, की बैठकें हुईं। इन सभी बैठकों में विभिन्न देशों ने अपने एमिशन्स को कम करने के लिए, एनर्जी ट्रांज़िशन करने के लिए और क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए कमिटमेन्ट्स

किए। हम लोगों ने भी किया। हालांकि हमारी जो per capita emissions हैं, वे दुनिया की पर कैपिटा एमिशन्स की एक-तिहाई हैं। Our per capita emissions are one-third of the global average. आज के दिन में हम देखें, तो एनवायर्नमेंट पर टोटल कार्बन डाईऑक्साइड का जो लोड है, उस टोटल लोड में हमारा कंट्रीब्यूशन मात्र 3.4 प्रतिशत है, जबकि हमारी आबादी, दुनिया की आबादी की साढ़े सत्रह प्रतिशत है। हमारा पर कैपिटा एमिशन और हमारा लीगेसी एमिशन कंट्रीब्यूशन, दोनों बहुत कम है। इसके बावजूद we have emerged as one of the leaders in energy transition. We have emerged; our country has emerged as one of the leading nations in climate action, in energy transition. We are the only major country, the only major economy, जिसके क्लाइमेट एक्शन sub 2 degree rise in global temperature compliant हैं। हम लोगों ने प्लैज ली थी - We had pledged in CoP 21 in Paris that by 2030, 40 per cent of our established power generation capacity will come from non-fossil sources. Mr. Deputy Chairman, Sir, you will be happy to know that we have achieved this target nine years in advance. We achieved this target in November, 2021. Today, our non-fossil fuel power generation capacity is 42 per cent of our total capacity. आज के दिन हमारी टोटल कैपेसिटी 408 गीगावॉट है। यानी चार लाख, आठ हज़ार मेगावॉट है। हमारी नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी, यानी कि renewable; solar, wind, hydro और नॉन फॉसिल फ्यूल में न्युक्लियर भी आता है, वह कम है- 6,800 मेगावॉट है- इन सबको जोड़कर हमारी नॉन फॉसिल कैपेसिटी 1 लाख, 73 हज़ार मेगावॉट है, जो कि हमारी इस्टैब्लिश कैपेसिटी का 42 परसेंट है। किसी भी देश ने इतनी तेजी से CoP-21 में दी गई प्लैज को achieve नहीं किया, हमने achieve कर लिया, because we achieved our target well in advance, इसलिए हमने CoP-26 में अपना ambition बढ़ाया। पहले हमने यह कहा था कि 40 परसेंट, we will achieve 40 per cent non fossil capacity by 2030. अब हमने यह कहा है कि we will achieve 50 per cent of our established capacity to come from non fossils by 2030. We have reduced our emissions intensity. इसी तरह से जो एमिशन इंटैन्सिटी हमने CoP-21 पेरिस में वर्ष 2015 में प्लैज की थी, that by 2030, we will reduce the emission intensity of our economy by 33 to 35 per cent by 2030. We have already achieved almost 30 per cent reduction. We shall over achieve that as well and that is why, in CoP-26 in Glasgow, we again upped our ambitions and we said that by 2030, we will achieve a reduction of 45 per cent in our emission intensity. So, we are doing well despite the fact that our per capita emissions are so low. But, that is because we believe in environment; our Government believes in environment. In fact, as a civilization, we have always believed in the environment. As a civilization, we venerate nature, the trees, water. So, it is in our blood, it is in our culture. This needs to be carried forward. एनर्जी ट्रांज़िशन में ways of generating electricity को हमने चेंज कर दिया है। But, that accounts for about 40 per cent of the emissions. 40 प्रतिशत एमिशंस पावर जेनरेशन के कारण होता है। But, we have to address the other sectors which account for 60 per cent of the emissions. Steel manufacturing, cement manufacturing; etc. All

these. Now, these are called hard-to-abate sectors. Now, we need to work out the way to do this! One way of course, is to electrify the economy so that people move away from coke and coal to electricity and at the same time, is to green the electricity. That is the strategy we are following. But, we also have to change our feedstock from fossil to non-fossil. I will give you an example.

Natural gas से अमोनिया बनाने के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है, कार्बन लोड बढ़ता है। हम जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग करते हैं, उसमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। अभी हाइड्रोजन की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, हाइड्रोजन जो बनता है, वह नैचुरल गैस से बनता है। उसमें भी CO_2 एमिट होता है। अगर हमको एनर्जी ट्रांजिशन करना है तो हमें fossil feedstock को non fossil से replace करना है। हमने प्लैज की है that by 2070 we will be net zero. We shall achieve that. We have achieved our targets in the past and we shall achieve it in the future as well. We are a leader in energy transition. That is not we are saying it, the whole world is saying it. Bloomberg called us the most attractive destination for investment in renewables. A body came out with the ranking of countries which are in the forefront of climate action. We stand fifth in that! Ahead of us, there are just four countries--Denmark, Sweden, Chile and another country. Only four countries with small economies! Amongst the major economies, we are the first in so far as success in climate action is concerned. So, Sir, we shall remain a leader. In order to do that, I have brought these amendments. इसी के लिए हम यह अमेंडमेंट लाए हैं। जैसे पेट्रोलियम रिफाइनिंग में में we use hydrogen drawn from the natural gas. The idea is to make green hydrogen here and thereafter replace grey hydrogen with that. We import the natural gas to make hydrogen. To replace that imported natural gas and stop the carbon emission, we will use green hydrogen. Of course, we will prescribe that replacement in stages. To begin with, there will be only small percentages like 5 or 10 and then going on thereafter. Similarly, for the production of fertilizers, we use ammonia made from natural gas and we import about 2-3 MT of ammonia. We also import more natural gas and make ammonia here. All that releases carbon dioxide into the atmosphere. We propose to replace that with green ammonia, made from green hydrogen. इसके लिए हम यह अमेंडमेंट ला रहे हैं, ताकि जो फीडस्टॉक है, उसमें हम बदलाव कर सकें। एक और सेक्टर है, जिसको हम इस अमेंडमेंट में एड्रेस कर रहे हैं और वह कन्स्ट्रक्शन सेक्टर का, बिल्डिंग सेक्टर का है। बिल्डिंग सेक्टर में जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, वे ऑलरेडी एड्रेस्ड है। कमर्शियल बिल्डिंग्स में लार्ज कमर्शियल बिल्डिंग्स, जिनका कनेक्टेड लोड 100 किलोवॉट से ऊपर है, वे ऑलरेडी एड्रेस्ड हैं। उसके लिए हम लोगों ने एनर्जी कन्जर्वेशन बिल्डिंग कोड बना दिया है। उसको करीब-करीब 20 राज्यों ने अडॉप्ट कर दिया है। अब जो भी कमर्शियल बिल्डिंग्स बनेंगी, उनको यह फॉलो करना होगा। इसी तरह से जो आजकल मल्टी-स्टोरी रेज़िडेंशियल फ्लैट्स बन रहे हैं, उनमें भी एनर्जी एफिशिएन्सी की बहुत गुंजाइश है, क्योंकि जो एमिशन्स है, उसका 24 परसेंट हाउसिंग सेक्टर, बिल्डिंग सेक्टर से आता है। उसको हम

इसमें इन्क्लूड कर रहे हैं, जो कि लार्ज बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इसमें हमारे ये दो मेन प्रोविज़न्स हैं। एक थर्ड प्रोविज़न कार्बन मार्किट का है। अभी हमारे यहां एक तरह का कार्बन मार्किट है, जैसे कि एमिशन इंटेन्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हम एक स्कीम लाए, उसे perform-achieve-trade कहते हैं। यह इंडस्ट्री के लिए लाई गई, जिसमें कि हम इंडस्ट्री के लिए एमिशन्स, एनर्जी कंज़म्प्शन और एमिशन इंटेन्सिटी का स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं। अगर उन्होंने उससे ज्यादा एचीव कर लिया, तो उनको हम एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट देते हैं और जो इंडस्ट्री उसको एचीव नहीं कर पाई, वह या तो एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट खरीदती है या फाइन देती है। महोदय, इसके अंतर्गत हमने ऑलरेडी 106 मिलियन टन प्रति वर्ष कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रिड्यूस किया है। हमने असेस किया है कि केवल चार साइकल्स में प्रति वर्ष इतना CO_2 एमिशन रिडक्शन हो गया। हम रिन्युएबल एनर्जी की आरईसीज़ देते हैं। इन सबको कम्बाइन करके हम कार्बन ट्रेड सिस्टम लाना चाहते हैं। क्योटो में कार्बन क्रेडिट सिस्टम लागू हुआ था, जो 2020 तक चला। पेरिस में अलग कार्बन क्रेडिट सिस्टम की एक नींव रखी गई है, उसके नियम बने। इसके अंतर्गत दुनिया में 40 कार्बन क्रेडिट सिस्टम ऑलरेडी हैं। हम इसमें कार्बन क्रेडिट सिस्टम लाना चाहते हैं, ताकि जिसको हम मैन्डेट करें या आप अपना कार्बन इंटेन्सिटी रिड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन रिड्यूस करेंगे, मैन्डेट करेंगे, अगर उससे ज्यादा रिडक्शन करता है, तो उसको कार्बन क्रेडिट देंगे, जो कि सेलेबल होगा। ये मेजर अमेंडमेंट्स हैं और कुछ और अमेंडमेंट्स हैं, जैसे हम पेनल्टीज़ में कुछ ग्रेडिंग कर रहे हैं। उसको रैशनल बना रहे हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएन्सी की जो गवर्निंग काउंसिल है, उसको ब्रॉड बेस्ड कर रहे हैं। इसमें ये सारे अमेंडमेंट्स हैं। ये सभी के सभी, हम लोगों का एनर्जी में जो मूवमेंट है, moving forward, making our system modern की ओर एक कदम है। We have already achieved universal access. हम लोगों ने जितने दिन में यूनिवर्सल एक्सेस अचीव किया है, by adding 29 million homes, वह इतनी तेजी से दुनिया में कहीं और नहीं हुआ है। We have already achieved a situation whereby the availability of power in rural areas has gone up from twelve-and-a-half-hours in 2015 to twenty-two- and-a-half hours today. We have already done it. My demand, as a result, has increased by about 20,000 to 25,000 megawatts per day on daily basis as compared to the previous year. All this is because we have strengthened the transmission system. So we have brought about major changes in the power system. We have reformed the power system also. This is one more step forward. So, I would recommend this Bill to the House.

The question was proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are three Amendments by Shri Elamaram Kareem, Dr. John Brittas and Dr. V. Sivadasan for reference of the Energy Conservation (Amendment) Bill, 2022 as passed by Lok Sabha to a Select Committee of the Rajya Sabha. Members may move the Amendments at this stage without any speech. Shri Elamaram Kareem, are you moving your Amendment?

SHRI ELAMARAM KAREEM (Kerala): I am not moving.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. John Brittas, are you moving your Amendment?

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I am not moving considering his past deeds of taking on communal forces when he was in Bihar.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, the Amendment is not moved. Dr. V. Sivadasan, are you moving your Amendment?

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Sir, I am not moving.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, you have not moved. So, all the three Amendments are not moved. The motion for consideration of the Bill is open for discussion. Dr. Abhishek Manu Singhvi.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA) *in the Chair.*]

DR. ABHISHEK MANU SINGHVI (West Bengal): Sir, as I rise broadly in support of the Bill, I am, nonetheless, struck by very unique features of the Indian legislative process and, more importantly, the governance process in the context of passing legislations. But first, Sir, with your permission, -- I have said it before in previous Governments, and I repeat it -- it is a minor procedural issue about Amendment Bills which carry roughly 80-100 Amendments, as this one does. This amends the Energy Conservation Act of 2001 with about 90-odd Amendments. Is it too much, Sir, to ask the Legislative Department irrespective of Government, to give us the original Act with brackets and footnotes as to what it would look if this Amendment was passed? The idea of going and locating each of these 90 Amendments in the original Act is a nightmarish exercise for somebody who wants to go into the detail and it is a very small thing. It is done by publishers who publish books of new Acts each year or twice a year with Amendments. I think every legislator, who wants to make a significant focused contribution, should be blessed with a copy of the original Act showing the Amendment and as they would look as if the Amendment Bill is passed and there is something so simple, but unfortunately, it has never been done for decades.

Sir, let me therefore, begin by complimenting the Government broadly on the initiative taken and say that the virtuous parts of the Bill which are desirable: (a) it brings building codes for energy efficient non-fossil fuel based constructions. So, non-fossil based construction will be encouraged and therefore, building codes have been amended or will be amended; (b) it is wider because it includes residences, commercial buildings, industrial spaces etc. so, it is all inclusive, no exclusions; (c) it expands the concept of carbon footprint emanations from buildings, vehicles, vessels, appliances and a much wider subset of human activity. Again, no exclusions. That is good.

Fourth, it creates agencies — not quite carefully; but, yes it does — for issuing Carbon Credit Certificates. It is a very important aspect which I will touch in a moment. Fifth, it seeks to create an ecosystem to buy and sell these Carbon Credit Certificates at all levels, supposedly, under a scheme, and there is some problem which I will address in a minute.

Of course, lastly, it penalizes with steep penalties those who don't comply with the requirements of reducing carbon footprints in all these activities — construction and non-construction areas.

But, Sir, equally, as in the well-known 1960s spaghetti Western movie — the Good, Bad and the Ugly — the good and the virtuous comes with not so good and, perhaps, the ugly.

The first phrase coming to my mind, as I holistically see the original 2001 Act, which this Bill seeks to amend, is that India is truly an over-legislated but under-enforced country. We tend to think that all our problems stop with legislation. And, we go back clapping and backslapping ourselves that we passed legislation. I will make that good in a moment.

The second striking facet is the hiatus between promise and performance, between preaching and practice, between *kathni* and *karni* which I will show you with the help of some statistics और मैं समझता हूं कि मैं और मंत्री महोदय अलग-अलग किताबें नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि आंकड़े तो अलग-अलग किताबों में अलग-अलग हो नहीं सकते, लेकिन इन्होंने जो आंकड़े दिये हैं, उनसे मेरे आंकड़े कुछ और हैं, भिन्न हैं। I have no doubt, Sir, about your good intentions. That is why I said that I rise broadly in support of the Bill. But, if you don't see the larger picture, the holistic picture, if you don't see the ground reality, then you know the old saying about good intentions — the path to hell is also paved with good intentions. तो ये कौन से विरोधाभास हैं, ये कौन सी विपरीत चीज़ें हैं, पहलू हैं। मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं और ये सिर्फ आंकड़े ही नहीं हैं, ये सच्चाई दर्शाते हैं।

पहला बिन्दु, इस बिल के अनुच्छेद 3 से 13 तक, यह जो संशोधन वाला बिल है, इसका 80 प्रतिशत या 90 प्रतिशत हिस्सा, अधिकतम हिस्सा यही 10 क्लॉज़ेज़ हैं। ये इसकी आत्मा हैं, इसका

शरीर हैं और यह ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी से डील करती हैं, जिसकी एक बहुत विशाल ब्यूरोक्रेसी बनाई गई है। इसमें वरिष्ठ सदस्य हैं, मंत्री महोदय हैं, उसमें 8-9 डिपार्टमेंट्स के बहुत वरिष्ठ सेक्रेटरीज़ हैं, लेकिन मैंने ध्यान से देखा तो 'खोदा पहाड़, निकला चूहा'। क्यों? क्योंकि अभी हमारी 25वीं पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है, उसमें लिखा है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर, 2021 में यही ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो आपके संशोधन बिल की सबसे स्पेशल फोकस वाली चीज़ है, इन 10 प्रावधानों में उसका खर्चा सिर्फ 54 परसेंट ऑफ बजट एस्टीमेट था, यानी कि आधे से थोड़ा ज्यादा - 54 परसेंट और उसके अगले वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर 2022 में फरवरी, 2022 तक 52 परसेंट है। जब आप इसका इस्तेमाल करने में 50 प्रतिशत सक्षम हैं तो इतनी विशाल ब्यूरोक्रेसी बनाना, इस बिल में इतने सारे अधिकार क्षेत्र देना, ऐसी संस्था को, जो अपने बजट ऐस्टीमेट का आधा या आधे से थोड़ा ज्यादा ही खर्च कर पा रही है और यह आपकी इस काम को करने के लिए एक मेन एजेंसी है।

दूसरा बिन्दु, साफ ऊर्जा जो है, इसका मकसद क्या है, जिसे आप नॉन फॉसिल या साफ ऊर्जा कहते हैं, कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है, यही आपका रियो में 1992 में उद्देश्य था, यही आपका क्योटो में 1997 में था, यही आपका पेरिस में 2015 में था, यही आपका कोपेनहेगेन में 2021 में था और यही अभी जब गये थे, शर्म अल शेख में 2022 में कुछ हफ्तों पहले था, लेकिन फिर 'कथनी और करनी' में विपरीतार्थक चीज़ें क्यों हैं? कुछ आंकड़े चौंकाने वाले हैं! आप इतनी बातें कर रहे हैं, अभी मंत्री महोदय ने इतनी चीज़ें आपको बताईं, लेकिन साफ ऊर्जा पर सब्सिडी आप कम कर रहे हैं और साफ ऊर्जा पर टैक्सेज़ आप बढ़ा रहे हैं! यह विरोधाभास नहीं है? जी.एस.टी. सोलर प्रोजेक्ट्स पर पांच प्रतिशत से 2021 में 12 प्रतिशत कैसे हुआ? हम यह प्रावधान 2022 में पास कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, मैं जानता हूं और मानता भी हूं कि चीन से आयात कम करना चाहिए, इसलिए आपने साथ-साथ बेसिक कस्टम्स ड्यूटी भी सोलर पैनल्स पर बढ़ा दी है। जी.एस.टी. अलग बढ़ाया है, आयात पर कस्टम्स ड्यूटी अलग बढ़ाई है।

5.00 P.M.

लेकिन आपको यह पता है कि हमारे बहुत सारे निर्माता इन सोलर पैनल्स के जो कंपोनेंट्स हैं, उन्हें आयात करके बाहर से मँगवाते हैं। आपके बटन दबाने से या आपके आयात की दर बढ़ाने से भारत आत्मनिर्भर नहीं हो जाता है, आपकी साफ ऊर्जा का अभियान सफर करता है।

तीसरा बिंदु, 2022 में अत्यंत महत्वपूर्ण "मैपिंग इंडियाज़ एनर्जी पॉलिसी, 2022" एक रिपोर्ट आई थी। मैं अभी इसी वर्ष की बात कर रहा हूँ। मैंने उसमें बड़ा चौंकाने वाला फिगर आया कि रिन्यूएबल सेक्टर, जिसको आप नॉन फॉसिल सेक्टर कहते हैं, उसकी सब्सिडी 2017 से 2022 के बीच में 60 प्रतिशत कम हुई है, 59 per cent to be exact. आपने 60 प्रतिशत सब्सिडी कम की है उस सेक्टर की, जिसको आप प्रोत्साहित करना चाहते हैं। इसमें एक अपवाद है। मंत्री महोदय ने सही कहा, वह एक अपवाद है, आपने बिजली वाले व्हीकल्स की सब्सिडी बहुत बढ़ाई है,

लेकिन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से बहुत ज्यादा व्यापक कॉसेप्ट है, यह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक सीमित नहीं है।

चौथा बिंदु, गलत ऊर्जा, फॉसिल फ्यूल में भी सब्सिडी कम हुई है, कोल, ऑइल इत्यादि, लेकिन आपको मालूम है कि आज भी फॉसिल सेक्टर को नॉन फॉसिल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से तुलनात्मक रूप से नौ गुणा ज्यादा, 900 परसेंट ज्यादा सब्सिडी मिलती है। आप इस देश को कैसे फॉसिल फ्री बनाएँगे?

पाँचवाँ बिंदु, पीएसयूज़ में आपके सात महारत्न हैं। वे जब नए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि वे फॉसिल फ्यूल के आधार पर इन्वेस्टमेंट न करें। उनके इन्वेस्टमेंट्स 2021 में और 2020 में 11 गुणा ज्यादा हुए हैं उन क्षेत्रों में, जहाँ फॉसिल फ्यूल का ज्यादा इस्तेमाल है, बनिस्बत रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन फॉसिल। माननीय, आज भी आपके आँकड़े जरूर थे, लेकिन 70 प्रतिशत भारत कोयले के आधार पर चलता है। आपके वित्तीय संस्थान, फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशंस, जो रुपया वितरण करते हैं, वे फॉसिल और कोयले आधारित प्रोजेक्ट्स पर 300 प्रतिशत ज्यादा करते हैं, बनिस्बत रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। ये सब चीजें सिर्फ कानून बनाने से हल नहीं होंगी। इन सब चीजों के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा, कानून हो या एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर हो। आज भी इस देश में 80 प्रतिशत सोलर पैनल्स आयात होते हैं। आपने उनकी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। आत्मनिर्भर वाली बात सही है, लेकिन आपके पास देश के अंदर ही निर्माण करने की क्षमता कहाँ है! ये सब आँकड़े हैं, ये स्पष्ट हैं। 2022 की जो इंस्टिट्यूट ऑफ एनर्जी रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि हमारा जो घोषित उद्देश्य है, माननीय प्रधान मंत्री ने घोषणा की है कि हम डबल करना चाहते हैं, 30 से 40 बिलियन यूएस डॉलर्स पर ईयर हमारा इन्वेस्टमेंट होना पड़ेगा, अगर हमारा 2030 का प्रधान मंत्री द्वारा घोषित उद्देश्य, 500 गीगावॉट रिन्यूएबल एनर्जी होना है। आज हमारा उससे आधा है। 2030 में 7 साल बचे हैं। अगर आप बीच के कई और फिगर्स देखें, 2022 की फिगर है 111 गीगावॉट जबकि 2022 के लिए आपकी घोषणा 175 गीगावॉट थी। प्रधान मंत्री की घोषणा है 2030 में 500 तक पहुँचना, तो आप कैसे पहुँचेंगे? कैसे पहुँच सकते हैं? कोई बटन दबा कर नहीं पहुँच सकते हैं। इसके लिए सिर्फ कानून बनाने और कानून में कुछ प्रावधान करने से हल नहीं निकलेगा। मैं यह कहना चाहूँगा कि statistics are not always lies, not damned lies. It is true that, like certain articles of clothing, what they reveal is interesting, but what they conceal is vital. But, they are sure, firm, factual indicators of where we are and where we are going. It is clear that all our declarations, all our promises at United Nations meetings, international conferences, international visits, targets spoken are not fulfilled each year and, in fact, cannot be fulfilled is known when we make the declaration. We cannot reach 500 GW by 2030. Figures have just been given. In 2022, we are at 111 GW, against the figure given of 175 GW. We cannot decrease carbon emissions by doubling our investments, by 15 to 20 billion US dollars per year. Where will we get the money from? You have yourself rightly recalibrated your 2050 promise to achieve net zero emissions. You have also already made it 2070.

Friends, all this, and the legislation in particular, ignore the holistic setting, what I call the elephant in the room. That elephant in the room -- we have just finished the Wildlife Bill -- is the larger issue of climate change and energy transition. One recent report estimates that climate change adverse movement costs you 3 to 10 per cent of GDP annually. We don't even have methods of evaluating how much GDP diminution is happening every year because of climate change. We cannot forget that climate change hits three rights the most -- first, the Right to Life; second, the Right to Food; and, third, the Right to Health. The Centre for Environment notes that on a climate change agenda, out of the 17 objectives of India published, 15 will not be met by 2022 end. These are hard facts, research things. I will give an example; vital issues like 100 per cent source segregation of dirt materials. Our forest cover has crawled upwards by 0.6 per cent from 2013. Our target was 33 per cent; we are at 24.6 per cent. These are hard, real facts. Even though I am supporting the Bill, it is important for you to do something about them. आपकी कथनी और करनी में फर्क है, जैसे सब्सिडी घटाना, टैक्स बढ़ाना, तो कथनी और करनी का जो गैप है, उसको आपको भरना पड़ेगा। आपने अभी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाया, लेकिन उसका बजट 1,800 करोड़ रुपये से घटा कर 1,000 करोड़ रुपये कर दिया। ऐसे में रिन्युएबल एनर्जी की बात करने का क्या फायदा हुआ? Sir, let me end by saying, we all know that nature does provide a free lunch but only to a limited extent, that is, if we control our appetite. We also know Gandhi*ji*'s equation between need and greed. We know well that the world is only marginally given by our fathers, it is largely borrowed from our children. The Bill needs to address the practical, statistical and holistic ground concerns, which I have outlined most humbly. The Bill needs to provide an impetus not merely by the cold letter of the law but by actual nitty-gritty. How, for example, will green buildings come up in the construction sector by merely amending construction codes? We all know that a green building costs 5 to 15 per cent higher investment when made, and recovery of their investments takes three to five years gestation period. Who will do it? Why will a builder do it? Why will an owner do it? The Bill, while rightly providing for carbon trading, a very good move, has not created or enabled either a regulator or a intermediary or a stock exchange. So, the expectation is that I will save carbon footprint and get a credit certificate, and I will sell it to my learned friend here. How it will happen, what the infrastructural structure for it is, I do not know; the Bill does not tell us. Entrusting this whole crusade for survival -- it is a crusade for survival, make no mistake about it — to whom; to the Ministry of Power and not to the Ministry of Environment. Is there not a clear conflict of interest? I do not want to mean it seriously, but in the old days there used to be a joke that you might want to make Dracula the head of a blood bank! Now, the Ministry of Power working to reduce

carbon emission is a major conflict of interest, Sir. And, at least, you should centralize; it is your own Government, it does not matter. At least, give it to the MoEF with some independence to stand up for environmental issues. So, hon. Chairman, it is a good Bill. It is a good start, at least, but much more needs to be done outside of the Bill, some more inside the Bill and the maximum to bridge the hiatus on the ground. All such initiatives are laudable, even if partial, incomplete or imperfect. And, certainly, this falls under all the three categories. Otherwise, if you don't even take this initiative, as Mr. Suzuki, the car-maker, rightly put it; when he said, if you don't give this primacy, you will be like a giant car heading towards a brick wall while everybody is arguing over where they should be sitting. We have been given a warning by science, we have been given a wake up call by nature. It is up to us to heed these calls by legislation as much as by executive action, and, I hope that will be done. Thank you very much.

श्री सुशील कुमार मोदी (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं 'द एनर्जी कंज़र्वेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2022' के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अभी श्री राज कुमार सिंह जी ने इस बिल के प्रोविज़ंस के बारे में विस्तार से बताया है।

महोदय, पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है। मुख्य रूप से जो ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रो क्लोरो-फ्लोरो कार्बन आदि जो सारी गैसेज़ हैं, ये वायुमंडल में जाकर जो रेडिएशन है, जो तापमान है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इसीलिए वायुमंडल का तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसी ग्लोबल वार्मिंग का ही परिणाम है कि कहीं बाढ़, कहीं सुखाड़, कहीं साइक्लोन है, कहीं अतिवर्षा है, कहीं गरमी है और कहीं ठंड है।

महोदय, इस ग्लोबल वार्मिंग में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी एक सेक्टर का है, तो वह एनर्जी सेक्टर है। ऐसा कहा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग में, जो कि कार्बन एमिशन के कारण हो रही है, उसमें 75 परसेंट कंट्रीब्यूशन केवल एनर्जी सेक्टर का है। दिन पर दिन ऊर्जा की डिमांड बढ़ती जा रही है, जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अभी-अभी सरकार ने करीब 2 करोड़, 68 लाख घरों को बिजली देने का काम किया है। आज भारत पावर डेफिसिट स्टेट नहीं है, बल्कि एक पावर सरप्लस स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है। हमारी जो पीक डिमांड है, वह 2 लाख, 15 हजार मेगावॉट है, जबकि हमारी इंस्टाल्ड कैपिसिटी 4,03,000 मेगावॉट है। देश में कहीं भी पावर शॉर्टेज नहीं है। अगर कहीं पावर शॉर्टेज है, तो वह ट्रांसमिशन के कारण है या अन्य कारणों से है। बिजली की कोई कमी नहीं है और बिजली की कमी के कारण कोई पावर शॉर्टेज नहीं है। अब तो बिहार जैसे राज्य में भी लोगों को 22-23 घंटे बिजली मिल रही है। यानी, कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे-जैसे हमारी अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है, वैसे-वैसे बिजली की डिमांड बढ़ रही है और जैसे-जैसे बिजली की डिमांड बढ़ रही है, वैसे-वैसे पॉल्यूशन, कार्बन एमिशन, ग्रीन हाउस गैसेज़ का एमिशन भी तेजी से बढ़ रहा है।

महोदय, पिछले 5 वर्षों में the Government has spent more than Rs.2,00,000 crore for improvement in the power infrastructure. 'One nation, one grid' के कारण देश में एक कोने से दूसरे कोने तक हम बिजली को तेजी से पहुँचा सकते हैं, लेकिन उपसभाध्यक्ष महोदय, क्या हम बिजली की खपत को कम कर सकते हैं? हम इसे कम नहीं कर सकते हैं। अगर हम दुनिया के बाकी देशों से तुलना करें, तो आज बिजली की पर कैपिटा जो कंजम्प्शन इंडिया के अन्दर है, वह 1,149 किलोवॉट पर ऑवर है। आज अमेरिका का एक आम आदमी कितनी बिजली कंज्यूम करता है? In America, per capita consumption is 12 times more than what we are consuming in India. It is seven times more than what is being consumed in Germany. यू.के. में पर कैपिटा कंजम्प्शन पाँच गुना ज्यादा है और चाइना भी करीब पाँच गुना ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। इस प्रकार हम ग्रोइंग इकोनॉमी हैं। हम ऊर्जा की खपत कम नहीं कर सकते। हमें और ज्यादा विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा चाहिए। एक आकलन है कि 2021-22 की तुलना में अगर 2031-32 को देखें, तो आज जितनी बिजली की डिमांड है, उसके लगभग 1.8 टाइम्स हमें और बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। तब हमें इतनी बिजली की आवश्यकता होगी। इस इनर्जी का जो इनपुट है, यह हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 85 परसेंट इम्पोर्ट कर रहे हैं, कुकिंग कोल इम्पोर्ट कर रहे हैं, जो कि स्टील और बाकी इंडस्ट्रीज़ में भी काम आता है। हम नेचुरल गैस, अमोनिया, ये सारी चीजें बड़े पैमाने पर इम्पोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए हमारे एनर्जी सेक्टर का जो इनपुट है, वह हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधान मंत्री चाहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बने, इसलिए कॉप के अन्दर सभी देश यह प्रण करते हैं, यह संकल्प लेते हैं कि वे कार्बन एमिशन को कैसे कम करेंगे। हरेक कॉप के अन्दर इन ग्रीन हाउस गैसेज़ के एमिशन को कैसे कम किया जाए, इसको लेकर दुनिया के देश संकल्प लेते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि हमें भारत में जो टारगेट 2030 में अचीव करना था, 2015 में पेरिस में जो कॉप-21 हुआ था, उसमें हमने जो कमिटमेंट किया था कि हम 2030 तक हमारी जो 40 परसेंट इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है, वह नॉन-फॉसिल सोर्सेज़ से होगी, लेकिन जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने बताया और मैं सदन को बताना चाहूँगा कि we have achieved this target nine years ahead of schedule. In the year 2021 itself, we have achieved the target, which was to be achieved in the year 2030.

महोदय, जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधान मंत्री थे, तब उनकी सरकार में यह एनर्जी कंज़र्वेशन एक्ट, 2001 आया था और आज जब नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधान मंत्री हैं, एनडीए की सरकार है, तब यह अमेंडमेंट बिल आया है। 2001 का जो ईसी एक्ट था, उसके अंदर जो लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट्स थीं, जो एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ थीं, उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स लागू की गई थीं। मैं सदन को बताना चाहूँगा कि large industries from energy intensive sectors के लिए जो पैट स्कीम्स थीं, उनके कारण 40 हजार करोड़ रुपए की एनर्जी की बचत हो रही है और 105 मिलियन टन कार्बन-डाइऑक्साइड के एमिशन को रोका जा सका है। हम जो सारे एप्लायंसेज़ यानी वॉशिंग मशीन, टीवी आदि यूज़ करते हैं, वे स्टार-रेटिंग वाले एनर्जी एफिशिएंट हाउसहोल्ड एप्लायंसेज़ यूज़ करते हैं।

Sir, 60 billion units of electricity is being saved per year only because of star rating of energy efficient household appliances. इसके कारण हमें 50 मिलियन टन कार्बन-डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करने में सफलता मिली है।

महोदय, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आने के बाद हमने 'उजाला योजना' प्रारंभ की थी और अभी तक 150 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए जा चुके हैं। इस एलईडी बल्ब के कारण 100 मिलियन कार्बन-डाइऑक्साइड के एमिशन को रोका जा सका है। इसी प्रकार से स्ट्रीट लाइटिंग में है। हर शहर के अंदर जो स्ट्रीट लाइटिंग की गई और उसमें एलईडी का इस्तेमाल किया गया, उसके कारण we have been able to save six billion units of electricity per year. Not only this, the overall impact of energy efficiency schemes is that electrical energy saving is 239 billion units. इसके अलावा थर्मल एनर्जी के कारण 21.40 मिलियन यूनिट्स की सेविंग हुई है। इस प्रकार से हम प्रति वर्ष टोटल एनर्जी कॉस्ट की जो सेविंग कर रहे हैं, वह 1.5 लाख करोड़ रुपए है। We are able to save Rs. 1.5 lakh crore as energy cost saving और 267 मिलियन कार्बन-डाइऑक्साइड के एमिशन को भी रोकने में भी हमें सफलता मिली है।

महोदय, रेलवे के क्षेत्र में माननीय प्रधान मंत्री जी ने तय किया कि दिसम्बर, 2023 तक इस देश के अंदर जितनी ब्रॉड गेज की लाइन्स होंगी, वे सब इलेक्ट्रिफाइड होंगी। ब्रॉड गेज पर कोई डीजल इंजन ट्रेन नहीं चलेगी। मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हम 1 अप्रैल, 2021 तक 71 परसेंट ब्रॉड गेज रूट्स को इलेक्ट्रिफाई कर चुके हैं और दिसम्बर, 2023 तक देश के टोटल ब्रॉड गेज रूट्स को इलेक्ट्रिफाई करने में सफल होंगे।

महोदय, 2014 में रेलवे का जितना इलेक्ट्रिफिकेशन था, उसमें दस गुना की वृद्धि हुई है। ये जो दो तरह के लोकोमोटिव्स होते हैं - डीजल लोकोमोटिव और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, यानी डीजल से चलने वाला इंजन और बिजली से चलने वाला इंजन। डीज़ल लोकोमोटिव का इस्तेमाल कम करने से in the year 2021, 25.48 लाख टन कार्बन डाईऑक्साइड के एमिशन को कम करने में हमको सफलता मिली है।

महोदय, इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो पता चलेगा कि जो कार्बन एमिशन है, उसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रिब्यूशन मोटर व्हीकल्स का है, जिनमें पेट्रोल का इस्तेमाल होता है। जब 2014 में नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधान मंत्री बने, उस वक्त पेट्रोल में इथेनॉल की जो ब्लेंडिंग थी that was only 1.4 per cent. Now, in 2022, the blending has increased from 1.4 per cent to 10.16 per cent. हमने तय किया था कि 2025 तक हम पेट्रोल के अंदर इथेनॉल की 10 परसेंट तक ब्लेंडिंग करेंगे। मैं सदन को बताना चाहूँगा कि हमने 2025 के पहले 2022 में ही 10 परसेंट का टारगेट अचीव कर लिया। यह है नरेन्द्र मोदी की सरकार! जो बोला, वह करके दिखाया। अब हमने 2025 का टारगेट 20 परसेंट का दिया है। जो टारगेट पहले 10 परसेंट का था, that will be 20 per cent blending in petrol by the year 2025. 2023 के मार्च से कुछ गिने-चुने पेट्रोल पम्पों पर 20 परसेंट ब्लेंडेड पेट्रोल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। महोदय, पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण 50,000 करोड़ के फॉरेन एक्सचेंज की बचत होगी। अगर हम इथेनॉल ब्लेंडिंग नहीं करते तो हमको पेट्रोलियम प्रोडक्ट इम्पोर्ट करना पड़ता, उस पर फॉरेन एक्सचेंज खर्च करना पड़ता। इस प्रकार, लगभग 50,000 करोड़ के फॉरेन एक्सचेंज की बचत करने में हमको सफलता मिली है। यह राशि किसको गई? यह राशि किसानों को गई, क्योंकि जो किसान गन्ना पैदा करता है

और जो अन्य चीज़ें पैदा करता है, उससे इथेनॉल बनता है। इसका एक ओर भारत के किसानों को लाभ मिला और दूसरी ओर हमारी 50,000 करोड़ के फॉरेन एक्सचेंज की बचत हुई है।

महोदय, हमने 'उज्ज्वला योजना' में नौ करोड़ फ्री गैस कनेक्शंस दिए थे। इसके पहले गाँव की महिलाएँ गोबर, कोयला और लकड़ी का इस्तेमाल करती थीं। हमने इसके द्वारा भी एलपीजी का हण्ड्रेड परसेंट कवरेज करके कार्बन एमिशन को कम करने का काम किया है। महोदय, सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मोबिलिटी को भी प्रमोट कर रही है। सरकार ने वर्ष 2030 तक टारगेट रखा है to electrify 70 per cent of all commercial vehicles, 30 per cent of all private cars, 40 per cent of all the buses and 80 per cent of all two-wheelers and all three-wheelers. हम 2030 तक इतने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाएँगे, ताकि मोटर व्हीकल्स के कारण जो कार्बन एमिशन होता है, उसको हम कम कर सकें। हम चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर प्रमोट कर रहे हैं। बैटरीज़ की लाइफस्पैन कैसे बढ़े, इस दिशा में सरकार काम कर रही है।

महोदय, एनर्जी कन्ज़र्वेशन एक्ट के फ्रेमवर्क में जो अमेंडमेंट लाया गया है, इसका टारगेट क्या है? इसका पहला टारगेट यह है कि कॉप-26 का जो गोल था, उस गोल को अचीव किया जाए। इस अमेंडमेंट के द्वारा कॉप-26 के गोल को हम अचीव करेंगे। इसका दूसरा टारगेट क्या है? जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ नॉन-फॉसिल फ्यूल यूज़ करती थीं, उनके लिए यह निर्धारित किया जाएगा कि आपको इतना परसेंट नॉन-फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप नॉन-फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आपको पेनेलाइज़ किया जाएगा। इसके तीसरे टारगेट के बारे में अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि इसके दायरे में अभी तक केवल कमर्शियल बिल्डिंग्स ही आती थीं, लेकिन अब ऐसी बड़ी रेज़िडेंशियल बिल्डिंग्स भी इसके दायरे में आएँगी, जिनका लोड 100 किलोवॉट से ज्यादा है। उनको भी अब एनर्जी कन्ज़र्वेशन एक्ट के तहत लाया जा रहा है, ताकि वे भी एनर्जी कन्ज़र्व कर सकें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Sushil *ji*, how much more time will you take?

SHRI SUSHIL KUMAR MODI: Ten minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): There are five more speakers from your party.

श्री सुशील कुमार मोदी : सर, मुझे थोड़ा सा अलाउ कर दीजिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Take another two to three minutes.

श्री सुशील कुमार मोदी: उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी कार्बन ट्रेडिंग का ज़िक्र कर रहे थे। अभी तक भारत में कार्बन की ट्रेडिंग नहीं होती थी। पहली बार इस बिल के द्वारा कार्बन की

ट्रेडिंग प्रारम्भ होने जा रही है। महोदय, कार्बन की ट्रेडिंग की चार हज़ार करोड़ रुपये की एक नई मार्केट क्रिएट होने जा रही है। अगर किसी को टारगेट दिया गया कि आपको 500 मेगावॉट सोलर एनर्जी यूज़ करनी है, या आप 500 मेगावॉट थर्मल बिजली यूज़ कर रहे थे, लेकिन आपने 400 मेगावॉट ही यूज़ किया, तो बचे हुए अंतर का आपको क्रेडिट मिलेगा। आप उस क्रेडिट को मार्केट में बेच सकते हैं। महोदय, इसके द्वारा एक नई मार्केट प्रारम्भ हो रही है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का बड़े पैमाने पर इन्वॉल्वमेंट होगा। डोमेस्टिक ट्रेडिंग प्रारम्भ हो रही है। महोदय, दुनिया की 40 कंट्रीज़ में ही कार्बन की ट्रेडिंग हो रही है, यूरोपियन यूनियन, चाइना, कोरिया आदि में हो रही है। इस बिल के पास होने के बाद जब इंडिया में कार्बन ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तब भारत कार्बन ट्रेडिंग करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा। महोदय, अगर आप एक टन कार्बन डाईऑक्साइड कम खर्च करेंगे, तो एक कार्बन क्रेडिट मिलेगा, जिसकी कीमत 500 से 800 रुपये प्रति यूनिट होगी। महोदय, मैं साथ ही साथ सदन को यह भी बताना चाहूंगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Sushilji, please.

श्री सुशील कुमार मोदी: उपसभाध्यक्ष महोदय, आप दो-तीन मिनट का समय और दे दीजिए। महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने कार्बन एमिशन को कम करने के लिए COP-26 में पंचामृत का एलान किया है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। उन्होंने क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए 5 चुनौतियां दी हैं कि किस तरह से हम उन चुनौतियों को अचीव करेंगे।

महोदय, जो सबसे बड़ी बात है, वह है LiFE (Lifestyle for Environment), प्रधान मंत्री जी और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने अक्टूबर, 2020 में Mission LiFE पर बात की। Mission LiFE यह है कि हर आदमी कार्बन एमिशन को कम करने के लिए क्या करे। महोदय, 75 एक्शन प्वाइंट्स दिए गए हैं, उदाहरण के तौर पर आम आदमी सीएनजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे, पानी को ठंडा करने के लिए फ्रिज और अन्य उपकरणों की बजाय मिट्टी के घड़े का इस्तेमाल करे, पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करने की बजाय...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Sushilji, please conclude.

श्री सुशील कुमार मोदी: महोदय, एक मिनट का समय और दे दीजिए। उनको क्लाउड में स्टोर करें, किचेन गार्डन को डेवलप करें और हम कम पानी की खपत वाली फसलों को उगाएं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि गांधी जी ने जो कहा था, "Earth can fulfil everybody's needs but not everybody's greed." पृथ्वी हर आदमी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सक्षम है, लेकिन आदमी के लोभ को पूरा करने के लिए नहीं है। सर, आधे मिनट में मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए। यह आवश्यकता को पूरा करने के लिए सक्षम है, इसलिए प्रधान मंत्री जी ने वेदों का एक श्लोक कहा, 'तेन त्यक्तेन भुंजीया' अर्थात् त्यागपूर्वक भोग करो, यानी हम जो युटिलाइज़ करें, उसका सोच-समझकर, आगे आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर त्यागपूर्वक भोग करें। इसलिए प्रधान मंत्री जी ने LiFE Mission का एलान किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

SHRI JAWHAR SIRCAR (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to place across the views of my party. We are not against any measure to conserve energy. We are completely with everyone in the nation for the conservation of energy. But as far as this particular Bill is concerned, it was placed to us in a hurry and we had submitted that it be sent to a select committee. We were procedurally debarred but I would still submit that we need a re-examination. I will explain as I move along. You need to re-examine the law. The intention is certainly good. The driving forces are also good. But the law as it stands today is full of defects. It empowers the bureaucracy at a wrong level. Both Mr. Minister and I have been in the Service and we know how bad certain levels of bureaucracy can be. But if you give over handlebars to them, they would obviously misuse. That is why we said, do not rush it. Take a little time. Send it to a Select Committee. Go through the implications of what you are saying. Let your good intentions be re-examined and we can proceed thereafter. But any case, we can go on with any one of the issues that you may feel.

First of all, your emphasis is on non-fossil fuel. Of course, we agree. Everyone agrees on non-fossil fuel but where are the non-fossil fuels? Green hydrogen is one of the greatest gimmicks that I have been hearing for the last few years. Where is the green hydrogen in abundant supply? Where is green ammonia in abundant supply? About biomass, we all took part in biomass campaign of *gobar* gas but anyway.

(MR. CHAIRMAN in the *Chair*.)

About ethanol, I know that we have a need for going over to non-fossil fuels but the need has to be accompanied by adequate capacities. Otherwise, we would take the car in the wrong direction.

On carbon credit, of course, it is a commendable move. But, on carbon credit, we are babies in the market. The world has gone over the carbon credit market and several studies have revealed the malpractices of it. Now, hon. Members have heard of this carbon credit market. Do you know what it is? In very simple terms, examination is held. Somebody gets 110. He can sell the 10 off to somebody who got 20. So, he can then add 10 to his 20 and he can pass the exam. सीधी बात! Do you understand? So, I would submit to the hon. Chairman that carbon credit is a well-intentioned move and is inevitable. It is desirable to a large extent but where is the examination or the studies of the misuse of carbon credit? I have explained to you in very broad intention that if the good student gets 110 and the bad student gets 20, he

can take 10 from him, add to him and pass. There are safeguards that have to be put in. We cannot accept it in its present form because most of it has been left to the bureaucracy to work out in the form of rules. Nothing has really been spelt out here in terms of actual legal provision. They have all been left to rule-making powers.

We have this provision of Energy Conservation Building Code. Again, it is a commendable idea, but then where is the social equity? When you talk of 100 Kilowatts, look at who is contributing to it. Where is the difference between an LIG, Low Income Group building, the cluster, and an HIG? We have to go in for differentiation. I would submit that if possible, if there is any possibility of getting cross subsidy, within the thing -- by the idea of cross subsidy I mean within the housing code -- please think of it.

About the bureau, again, you are increasing their powers. I am not so much bothered about the senior officials of the bureau. I am more bothered about the instructions that go from there and the scope of misuse. You know, the building markets all over India are supposed to be, क्या कहते हैं, लोग कहते हैं दो नम्बरी। There is something attached to the building market. I can't explain it anymore. You are now introducing one more player into the building market. So, these are the points on which we had sought for reconsideration and I would still submit that with your kindness, if you can send it for reconsideration, we can come to the same Bill in the next Session with the wisdom of the parties put in. I mean when we work in the Committees, we do not work as a party. We work as parliamentarians.

The State Electricity Regulatory Commissions are being assigned certain duties. I would still submit to get into a little more detail to see whether the State Electricity Commissions need to be assisted to reach that capacity of exercising the powers under the Act. We are thankful that in one case, there is some amount of attention on the State. But, Sir, we have to look at the picture in a little broader light. We are talking of energy conservation here; we are talking of environment here; we are talking of saving the environment and right now, the same Government has given order for slaughtering 130 sq. Kms. of the great Nicobar Islands. The wildlife and the biodiversity there, the flora and fauna are ir-replaceable. But, they are allowing concrete boulders and concrete constructions to take place. We cannot have so much of dichotomy. On the one hand, you come and introduce a Bill saying that we are dying because of the environment and on the other hand, you take active steps to destroy the ecologically fragile region of the Andaman & Nicobar Islands. I have a feeling, I may be wrong, I may be right that there is an excess of renewable energy in certain parts of India, and they need to be transferred through compulsive methods so that they are sold. I am told that renewable energy is facing problems of both

supply and further extension because the grids are in a terrible condition. The Ladakh Project of solar energy had to be abandoned because the grid position is very poor. Mr. Chairman, Sir, with your kind permission, I reiterate that renewable energy, as such, needs to be looked into afresh. The area of renewable energy and its production and distribution need to be looked in afresh and not be rushed through. Mr. Minister, you have taken commendable steps in that direction. But, I will still submit that it is not a question of individual effort, it is a question of the system functioning. You are aware more than me as to what are the difficulties of the renewable energy. I have been given to understand that in certain areas where renewable energy production has reached such a stage that DISCOMS don't pick it up. But, under your compulsion, DISCOMS will have to pick up. Pick up and take it where? You have the compulsive power. The additional compounded problem is that DISCOMS don't pay the renewable energy producers because they don't get their own payment. It is all a very complex thing and you are handling one of the most difficult subjects in India. I appreciate it. But, the fact is that we had been pleading and we still continue to say that let us go through the provisions, and there is no point in rushing a national task over a few minutes of debate. We have spoken about the buildings, LIG and HIG. I don't know whether I have time to get into the provisions but I will mention just a couple of provisions. I was getting through Section 4 which is basically about the leadership part, the Governing Council. We can't quarrel with the Government about as to how many people you are going to fit in but at one place, instead of 25 or 26, you are taking it up to 31. Now, a committee of 31 hardly functions. A committee of 31 people means 31 people will come with 60 to 64 people and all they will do is to waste hours and keep minutes. That is all. They will waste hours and keep minutes. Let us get in for more practical methods, a steering committee to move things around. You have the powers of the Central Government. You have not spelt out Section 13 in very great details. The sparse wordings makes me a little uncomfortable, a little uncomfortable over Section 13. It should not be another place where federalism is tilted and the Central Government is given over-riding powers over the State Government. We need to examine them. I am not telling you to throw the baby with the bathwater. We are saying that let us save both the situations and let us go in for a re-examination of the Bill. You have put in clauses like the *haveldari* clauses about banning of sale of deceptive instruments about those who don't conform to standards. *(Time-bell rings.)* Again, very commendable intentions. But once you leave it to the inspectorate, God help all of us. These are the reasons for which I submit, your honour, that we need to re-examine the Bill. It is full of good intentions. There are certain very good sections, but there are sections that scare us.

That scare me as a citizen of India, that scare me as somebody, who has worked in the bureaucracy for 40 years because we have seen how the things function; how the best of intentions are hijacked into oppressions, harassment and corruption. Please don't bring a good intention to such a pass. Thank you, Sir,

MR. CHAIRMAN: Well, the hon. Member and the hon. Minister, both have one thing in common, the huge bureaucratic experience. And I am sure there will be synergical approach between them, trained as they are for decades.

Hon. Members, the discussion on the Energy Conservation (Amendment) Bill, 2022, will now continue on Monday. I will now start with Special Mentions. Dr. Kanimozhi NVN Somu.

SPECIAL MENTIONS

Need to establish the National Centre for Animation, Visual Effects, Gaming and Comic at Chennai

DR. KANIMOZHI NVN SOMU (Tamil Nadu): Sir, in the Budget 2022-23, the Government had announced setting up 'Animation, Visual Effects, Gaming and Comics' (AVGC) taskforce to build domestic capacity to serve Indian markets and global demand. Chennai is universally acknowledged and recognized as India's Hollywood, as a leader in film production with tremendous scope for visual effects and special effects.

Chennai leads from the front in audio, video production, post production processing activities like digital recording, mastering, dubbing and animation. Hundreds of films are being produced in our country every year and Chennai is a hub of film and television industry, social media networks and OTT platforms, which provide tremendous opportunities for those who have penchant for visual art.

It could also open up new avenues. The potential for job opportunities in the AVGC sector is humongous. The number would vary between 1 to 1.5 lakh job opportunities for the entire space. The AVGC sector is growing rapidly, but there is a void for good programmers, graphic designers.

Sir, in keeping pace with the developed countries where they have invested substantially, it is necessary that our country to create adequate workforce and also provide job opportunities for youngsters in this field.